# ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा


पेजः 4

**अंटार्कटिका के नाजुक इकोसिस्टम में पहुंचा प्लास्टिक**

रविवारीय, 05 - 11 जूलाई 2020 वर्ष- एक, अंक-48, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

## संक्रमण की वजह से श्रावणी मेला का आयोजन संभव नहीं :मुख्यमंत्री

रांची :कोरेाना संक्रमण के खिलाफ हमें और लड़ाई लड़नी है। ऐसे में श्रावणी मेला नजदीक है। श्रावण मास में पूरे देश से श्रद्धालु बाबाधाम और बासुकीनाथ आते हैं। राज्य सरकार राज्यवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। सरकार संक्रमण काल में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती, जिससे झारखण्ड महामारी के बुरे दौर में चला जाये। संक्रमण को हल्के में नहीं लेना है। इसके प्रति गंभीरता जरूरी है। पूरी सतर्कता से कार्य करना है। इस वजह से राज्य सरकार ने श्रावणी मेला का आयोजन इस वर्ष नहीं करने का निर्णय लिया है। हमें सामाजिक व्यवस्था और परंपरा को स्थगित रखते हुए कार्य करना है।

ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी संक्रमण का दौर है और मंदिर में श्रद्धालु नहीं आ रहें हैं। सिर्फ पुजारी भगवान की आराधना कर रहें हैं। ऐसे में मंदिर परिसर को हाई जेनिक बनाएं

# नौ लाख पेड़ काटे जायेंगे

**मुख्य संवाददाता**

**उड़िसा के क्योंझर जिले के गंधलपाड़ा गाव का ये जंगल लौह अयस्क खनन के लिये काटा जायेगा**

**जंगलों को उजाड़ कर खनन औश्रार ोग धंधे तो लग रहे हैं, पर दुर्घटनायें भी बढ़ रही हैं**

पिछले साल जब ब्राजील के जंगलों में आग लगी थी तब सारा विश्व इसे लेकर चिंतित था। ब्राजील के अमेंजन के जंगलों से इतना ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है कि इसको दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन के जंगलों में लगी आग के बारे में आरोप लगाया गया था कि इसे स्वयं ब्राजील के राष्ट्रपति ने लगवाया था ताकि जंगलों का सफाया हो जाये और वहां फैक्ट्रियां लगायी जा सके।

उड़ीसा के क्योंझर जिले के गंधलपाड़ा गांव में भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। यहां उड़ीसा सरकार ने खनन के लिये नौ वर्गकिलोमीटर भूमि में लगे साल के घने जंगलों को निलामी में देकर काटने का निर्णय ले लिया है और यहां से अब तकरीबन नौ लाख साल व अन्य पेड़ों को काटा जायेगा। पिछले साल भी इन जंगलों को खनन के लिये काटने की बात हुई थी लेकिन तब यहां के आदिवासियों के प्रचंड विरोध को देखते हुये मामले को कुछ दिनों के लिये टाल दिया गया था। लेकिन अब राज्य सरकार के निर्णय का विरोध करने कोई आगे नहीं आ रहा है और सभी ये स्वीकार कर चुके हैं कि ये घने जंगल अब कुछ ही दिनों में काट कर साफ कर दिये जायेंगे।

यहां रहनेवाले आदिवासियों को कहना है कि शुरू से ही ये जंगल उनकी आजीविका के मुख्य साधन थे। अब यहां खनन होगा तो सरकार और कंपनियां तो मालामाल होंगी, पर हम बर्बाद होते जायेंगे।

अब तक लॉकडाउन में पर्याव्रण के साफ स्वच्छ होने की खबरें सुर्खियों में थी पर अब शांत और स्वच्छ रहने वाला यह इलाका अंततः प्रदूषण , खनन की मार से तबाह हो जायेगा।

बीते 7 मई को विशाखापत्तनम में एलजी पॉलिमर प्लांट में स्टाइरीन गैस के रिसाव के कारण 14 लोगों और लगभग 22 पशुओं की मौत हुई, 400 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फैक्ट्री से 1.5 से 3 किलोमीटर की परिधि में रह रहे 2000 से अधिक लोगों को अपनी जगह खाली करनी पड़ी। शुरू में यह कहा गया कि लगभग 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद अचानक संयंत्र को चालू करने से मशीन के निचले और ऊपरी हिस्से के तापमान में अंतर के कारण जहरीली भाप बनी, जिससे दुर्घटना की स्थितियाँ पैदा हुई। बाद में दुर्घटना के कारणों पर और विस्तृत छानबीन करने पर पता चला कि एलजी पोलीमर्स बिना पर्यावरण मंजूरी के, मात्र आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा दी गयी 'फास्ट ट्रैक' सहमति के आधार पर ही काम कर रही थी। पर्यावरण मंजूरी की कमी के कारण एलजी पॉलीमर प्लांट के प्रबंधन में तमाम अनियमितताएँ रही, जो दुर्घटना का कारक बनी। लॉक-डाउन के ही दौरान केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआ-ईए) अधिसूचना प्रस्तावित की है। नया मसौदा फिलहाल सार्वजनिक टिप्पणियों के चरण में है। उक्त मसौदा लागू किए जाने की स्थिति में पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना, 2006 पर प्रभावी होगा। जाहिर है, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिसूचना जरूरी हस्तक्षेप की दरकार रखती है ताकि पर्यावरणीय सुरक्षा के मानदंडों की मजबूती को सुनिश्चित किया जा सके और विशाखापत्तनम या भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

नई अधिसूचना को हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कोयले की कमर्शियल माइनिंग के आलोक में भी देखा-समझा जा सकता है। ऐसा लगता है कि औद्योगिक निवेश के लिए किसी भी कीमत पर तत्पर वर्तमान सरकार ने मानवाधिकारों से लेकर पर्यावरण सुरक्षा संबंधी सभी मानदंडों को पूरी तरह से अनदेखा करने का मन बना लिया है। तो आखिर किसके फायदे के लिए हो रहा है पर्यावरण नियमों में बदलाव? क्या आपदा पूंजीवाद के दौर में अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जनता संघर्ष करेगी?

# सावन में ऑनलाइन दर्शन देंगे पहाड़ी बाबा

**भगवान शंकर की पूजा-अर्चना का ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे**

- एसडीओ रांची एवं पहाड़ी मंदिर समिति के प्रतिनिधियों के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक।
- कोरेाना के रोकथाम हेतु सर्वसम्मति से जनहित लिया गया निर्णय
- पहाड़ी मंदिर में धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं
- केवल पुजारी करेंगे विधिवत पूजा अर्चना
- श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं
- ऑनलाइन दर्शन की रहेगी व्यवस्था
- भगवान शंकर का दर्शन घर बैठे, कर पाएंगे श्रद्धालु

**धार्मिक आयोजन पर रोक**:कोरेाना की रोकथाम हेतु सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी सावन के महीने में पहाड़ी मंदिर में किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं जाएगा।

**श्रद्धालुओं के लिए रहेगी ऑनलाइन दर्शन सुविधा** :पहाड़ी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद जरूर रहेगा परन्तु वे ऑनलाइन बाबा भोले की दर्शन कर पाएंगे। घर बैठे ही श्रद्धालु भगवान शंकर का दर्शन कर पाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी रांची लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में पहाड़ी मंदिर समिति के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंदिर संचालन को लेकर सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

**पुजारी करेंगे पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित**: मंदिर के पुजारी के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मंदिर के पुजारी ही केवल भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना का कार्य सम्पन्न करेंगे। पूर्व की भांति ही श्रृंगारी पूजा भी पुजारी के माध्यम से किया जाएगा।

# जीवाणु खाद :पोषक तत्व प्रबंधन का सस्ता व उत्तम साधन

संवाददाता रांचीः आधुनिक कृषि में जीवाणु खाद का महत्व बढ़ता जा रहा है। फसलों में इसके प्रयोग से उर्वरकों की खपत को कम और पर्यावरण के नुकसान से बचा जा सकता है। फसल उत्पादन लागत में कमी एवं स्फूर उ-र्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाई जा सकती है।

बीएयू के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग के अध्यक्ष डॉ डीके शाही बताते है कि वास्तव में जीवाणु खाद बैक्टीरिया, कवक एवं नील हरित शैवाल आदि का सक्रिय प्रभावी विभेद की पर्याप्त संख्याओं से युक्त उत्पाद है। जिसे मिट्टी में मौजूद माइक्रो ओर्गेनिस्म का वैज्ञानिक तरीकों से चुनाव कर प्रयोगशाला में उत्पादित किया जाता है। इनमें राइजोबियम कल्चर, एजेटोबेक्टर कल्चर,फॉस्फेट विलेयक जीवाणु (पीएसबी) कल्चर, एजोस्पाइरिलम कल्चर तथा नील हरित शैवाल आदि प्रचलित प्रमुख जीवाणु खाद है।

**राइजोबियम कल्चर**: सभी दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की छोटी -छोटी गाठें होती है, जिसमें राइजोबियम रहते है। ये जीवाणु हवा से नेत्रजन व अघुलनशील गैस लेकर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते है। इस कल्चर के उपयोग से नेत्रजन खाद की बचत, उपज में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि तथा भूमि की उर्वरता का विकास होता है। इससे करीब 35-40 किलो नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल को मिलता है, जो करीब 75-85 किलो यूरिया के समतुल्य है। इसके प्रयोग से दलहन, तेलहन, चारा फसल के अलावे अन्य दूसरी फसलों को भी नेत्रजन प्राप्त होता है। इसमें सबंधित फसल के राइजोबियम कल्चर से फसल बीज को उपचारित कर बीज की बुआई की जाती है। बीजोपचार हेतु प्रति एकड़ 200 ग्राम (दो पैकेट) राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है।

**एजेटोबेक्टर कल्चर**: यह जीवाणु मिट्टी में पनपते है और पौधा के जड़ परिसर में मुक्त रूप से पाया जाता है। इसमें गाठें नहीं होती है। यह बिना दलहन वाली विभिन्न फसलों को वायुमंडलीय नेत्रजन उपलब्ध करने में सक्षम है। यह बीमारी पैदा करने वाले फफूंद के नियंत्रण और पौधे के वृद्धि में हारमोन व विटामिन के निर्माण में तथा सब्जियों में होने वाले बीमारी से बचाव में सहायक होता है। इस कल्चर का प्रयोग अनाज वाली फसलों जैसे - धान, मक्का,ज्वार, जौ, गन्ना एवं गेहूँ तथा सब्जी फसलों जैसे - बैंगन, टमाटर, आलू, फूलगोभी, पत्तागोभी, भिंडी के अलावे तेलहनी फसलों इस जैसे - सरसों, तीसी एवं सूर्यमुखी के लिए करते है। इसके प्रयोग से 25-30 किलो नेत्रजन यानि करीब 55-65 किलो यूरिया की बचत की जा सकती है। एजेटोबेक्टर कल्चर से फसल बीज को उपचारित कर बीज की बुआई की जाती है। बीजोपचार हेतु प्रति एकड़ 200 ग्राम (दो पैकेट) एजेटोबेक्टर कल्चर की आवश्यकता होती है।

**पीएसबी कल्चर**: फसल में स्फूर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एसएसपी/डीएपी का प्रयोग किया जाता है। जो काफी हद तक अघुलनशील होता है। पीएसबी कल्चर इसी अघुलनशील स्फूर को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराता है ।यह पौधों में फूल एवं बीज बनने, जड़ बनने व इसके फैलने में मदद करता है। इसका उपयोग दलहन, तेलहन, चारा, अनाज एवं सब्जी फसलों में स्फूर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए करते है। इसके उपयोग से उपज में 10-25 प्रतिशत की वृद्धि होती है। झारखण्ड की अम्लीय भूमि में रा-इजोबियम कल्चर के साथ पीएसबी कल्चर के प्रयोग से अधिक लाभ होगा। बीजोपचार हेतु प्रति एकड़ 200 ग्राम (दो पैकेट) पीएसबी कल्चर की आवश्यकता होती है।

.....शेष पेज तीन पर

# बीएयू ने अरहर की उन्नत किस्मों की खेती को बढ़ावा देने की पहल की

अजय कुमार

***132 किसानों के कुल 20 हेक्टेयर भूमि में अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण (एफएलडी)अरहर के 5 उन्नत किस्मों की खेती को बढ़ावा***

रांचीः आईसीएआर, नई दिल्ली द्वारा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर के सौजन्य से बिरसा कृषि वि-श्वविद्यालय में अखिल भारतीय समन्वित अरहर शोध परियोजना चलाया जा रहा है। इस परियोजना के तहत चालु खरीफ मौसम में रांची जिले के चान्हो प्रखंड के कुल्लू और चुटिया गाँव के 50 किसानों के कुल 7 हेक्टेयर भूमि और मांडर प्रखंड के ब्राम्बे गाँव के 12 किसानों के कुल 3 हेक्टेयर भूमि में अरहर किस्म आईपीए - 203 का अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण (एफएलडी) कराया जायेगा।

इस परियोजना के तहत जनजातीय उपपरियोजना (टीएसपी) के अधीन चान्हो प्रखंड के कंजागी और मंडिया गाँव के 40 जनजातीय किसानों के कुल 7 हेक्टेयर भूमि और मांडर प्रखंड के सकरपदा गाँव के 30 किसानों के कुल 3 हेक्टेयर भूमि में अरहर के 5 किस्मों जैसे आईपीए - 203, बीएयू पीपी 09-22, बहार, बिरसा अरहर-1 तथा जेकेएम -189 पर अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण (एफएलडी) कराया जायेगा।

बुधवार एवं गुरूवार को परियोजना अन्वेंशक डॉ नीरज कुमार के नेतृत्व में बीएयू वैज्ञानिकों में चान्हो प्रखंड के कुल्लू, चुटिया, कंजागी और मंडिया गाँव तथा मांडर प्रखंड के सकरपदा एवं ब्राम्बे गाँव का दौरा कर एफएलडी के लिए 62 प्रगतिशील किसान तथा 70 जनजातीय किसानों का चयन किया। किसानों को एफएलडी के लिए अरहर के 5 उन्नत किस्मों के बीज अ वितरण किया।

मौके पर बीएयू वैज्ञानिकों के दल ने किसानों को टांड़ भूमि में अरहर का सही समय पर बुआई के फायदे, अरहर बुआई से पहले

कतार में चुने का प्रयोग, बीजोपचार तथा राईजोबियम कल्चर से बीज का उपचार तथा खेतों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग की तकनीकी जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने बताया कि बुआई के 10 दिन बाद बीज की बुआई कर गैप फिलिंग किया जाना चाहिये। खेतों में बीजों के सही अंकुरण और खड़ी फसल पर खरपतवार नाशी के उपयोग से अरहर की सफल खेती की जा सकती है। दल में डॉ एस कर्मकार, डॉ विनय कुमार तथा डॉ एचसी लाल शामिल थे।

परियोजना अन्वेषक डॉ नीरज कुमार ने बताया कि प्रदेश के करीब 2 लाख हेक्टेयर भूमि में अरहर होती है। इसकी राष्ट्रीय उत्पादकता स्तर 832 किलो/हेक्टेयर के मुकाबले झारखण्ड का उत्पादकता स्तर 1095 किलो/हेक्टेयर है ।जिसे ध्यान में रखकर उन्नत किस्मों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

# महज एक नदी नहीं बल्कि मां स्वरूपा है गंगा....

**डॉ.कृष्ण कुमार मिश्र**

***आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पीएच-डी. की उपाधि प्राप्त की। आप टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई के होमी भाभा विज्ञान केन्द्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। लोकप्रिय विज्ञान लेखक के रूप में आपकी अपार ख्याति है जोकि हिन्दी में आपके व्यापक लेखन से निर्मित हुई है। आपके 250 से अधिक लेख तथा 22 पुस्तकें प्रकाशित हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार, होमी जहाँगीर भाभा स्वर्ण पुरस्कार, शताब्दी सम्मान, राजभाषा भूषण पुरस्कार, इस्वा सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित डॉ.मिश्र मुंबई में निवास करते हैं।***

गंगा भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण नदी है। इसे 4 नवम्बर 2008 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में से होकर बहती है। इसकी कुल लम्बाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में स्थित गोमुख नामक ग्लेशियर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा के पास जाकर सागर में मिलती है। गंगा नदी के किनारे कई प्रमुख शहर स्थित हैं जिनमें हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, पटना, आदि शामिल हैं। राज्यवार देखें तो यह नदी उत्तराखंड में 450 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर, बिहार में 405 किलोमीटर, झारखंड में 150 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। गंगा का नदी क्षेत्र 8,38,200 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत भूभाग पर फैला है जो कि पूरे भारत में सबसे विशाल नदी क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी में सागर में समाहित होने से पूर्व गंगा नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे सुन्दरवन कहा जाता है। यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ और तलछट से परिपूर्ण है जो करीब 59ए000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मान्यता है कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। भागीरथी नदी गोमुख नामक ग्लेशियर से निकलती है जो कि गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर हिमालय में स्थित है। अलकनंदा हिन्दुओं के पवित्र तीर्थ तथा चारो धामों में से एक बदरीनाथ धाम से होकर गुजरती है। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा में मिलती है। इस स्थान को संगम के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इसीलिए यहां के संगम को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं तथा प्रयागराज को संगमनगरी भी कहा जाता है। संसार का सबस बड़ा मेला, कुंभ मेले के नाम से प्रयागराज में लगता है। हजारों वर्षों से लग रहे इस अद्वितीय मेले को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। मानवीय हस्तक्षेप से गंगा का जल स्तर समय के साथ कम होने लगा है। वाराणसी में गंगा उत्तरवाहिनी हैं तथा रुककर बहती हैं। एक समय वहां गंगा की गहराई 60 मीटर तक हुआ करती थी। वह अब घटकर कई जगह 10 मीटर तक हो गई है। कानपुर और पटना के बाद गंगा अब वाराणसी के घाटों से भी दूर हट रही हैं। कई एक जगहों पर यह विस्थापन इतना अधिक है कि नियमित स्नानार्थियों को नाव से गंगा पार जाकर डुबकी लगाने की नौबत आ गई है। गंगा तो अब अपना रास्ता भी बदलने लग गई है। हरिद्वार में मूल धारा अब तीन दशक पहले की तुलना में आधा किलोमीटर दूर हो गई है। बिहार में कुछ जगह गंगा ढ़ाई किलोमीटर विस्थापित हो गई है ।गोमुख ग्लेशियर भी धीरे-धीरे घटने लगा है। पर्यावरणविदों का तो यहां तक कहना है कि गंगा के पर्यावरण पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो यह संभव है कि वर्ष 2050 तक गंगा का अस्तित्व ही न रहे। गंगा हमारे देश की महज एक नदी ही नहीं है बल्कि यह कोटि-कोटि जनों की भावनात्मक आस्था का आधार भी है।

जारी..*इलेक्ट्रोनिकी आपके लिये से साभार*

# एप में अटकी जिंदगी

चाइनीज एप के बैन होने से हमें फौरी सुकून तो मिल सकता है, पर ये कोई स्थायी समाधान नहीं है । ये एप हमारी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यो के बजाय मनोरंजन के नाम पर बकवास चीजों में खर्च करवाते हैं। टिकटॉक या अन्य चाइनीज एप बैन हो गये लेकिन इनके जैसे देशी एप विकल्प के तौर पर उपलब्ध हैं जो निकम्मेपन को बढ़ावा देता रहेगा। आखिर इन एप से कोई स्वस्थ मनोरंजन भी नहीं होता उल्टा हमारा युवा वर्ग घंटो मोबाइल में आंखे गड़ाये रहता है। इसके कारण मैदान में जाकर युवाओं और बच्चों का खेलना कम हो गया है, कम उम्र में आंखों पर चश्मा लगने से लेकर स्मार्टफोन की चाह में दुखद घटनाओं का होना बढ़ गया है। हाल ही में एक खबर आयी कि तेरह साल के एक बच्चे से सिर्फ इसलिये आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पिता ने स्मार्टफोन के लिये उसे कुछ दिन रूकने को कहा था।

इसके पक्ष में दलील देने वाले कुछ भी कहें, पर हम ये स्पष्ट महसूस कर सकते हैं कि स्मार्टफोन और इसके एप ने हमारी जिंदगी को बेढंग कर दिया है। दरअसल मोबाइल का मूल उपयोग बातचीत करना ही था लेकिन जैसे ही इसमें इंटरनेट, कैमरा, आडियो वीडियो रिकार्डिंग प्ले करने की सुविधा के साथ ही गेम और मनोरंजक एप के फीचर जुड़े यह स्मार्ट होकर आम लोगों के हाथ में एक विस्फोटक सामान की तरह हो गया है। ज्यादतर भारतीय युवा इनमें किसी न किसी एप के पीछे बौराया हुआ है।

बेहतर हो सरकार सिर्फ चीन को सबक सीखाने पर ही ध्यान देने के बजाय मनोरंजन के नाम पर बकवास परोस रहे इन एप को ही बैन कर दे चाहे वो देशी हों या विदेशी।

टिकटॉक या इसके जैसे ही कोई भी माबाइल एप हमारे समय, स्वास्थ्य और मानसिक स्तर को खराब करते रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है कि टिकटॉक के बैन होने के बाद संजीदा किस्म के लोग भी कह रहे हैं कि इसके बैन होने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गये हैं। और तो और इस बेहूदा एप पर नाचने गाने वालों को स्टार का दर्जा तक प्राप्त है।

कई ऐसे वाकये भी हुये हैं कि टिकटॉक के लिये वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ की जान तक चली जाती है, बहुत सारे लोग इन एप की गिरफ्त में कुछ इस तरह से हैं कि उनकी जिंदगी इसी तमाशे के इर्द गिर्द घुमती रहती है। ऐसे में हमारा युवा वर्ग मनोरंजन के नाम पर इन मोबाइनल एप के चक्कर में अपनी वास्तविक क्षमताओं को भूल कर आभासी दुनिया में जी रहा है। और चीन खुद अपने यहां इनमें से ज्यादतर को बैन किये हुये है।

# अर्थव्यवस्था के बाद पर्यावरण का क्या?

*मुरलीधर*

**कोविड संकट के बीच भारत का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर्यावरण के लिहाज से दुनिया के पांच सबसे खराब पैकेजों में एक बताया गया है। सरकार का दावा है कि यह धनराशि खराब अर्थव्यवस्था में जान फूंकेगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा?**

कोरोना संकट के बीच दीर्घ लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हुए भारी नुकसान से उबरने के लिए भारत सरकार ने पिछले दिनों 20 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज जारी किया था। इसमें निर्माण और कोयला आधारित इकाइयों पर अधिक निवेश पर जोर दिया गया था। ये ऐसे उद्योग हैं जहां निवेश का अर्थ है कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देना। जानकारों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान को इस तरह के पैकेज और पीछे धकेलेंगे और दुनिया की हालत और अधिक चिंताजनक होती जाएगी। लेकिन भारत ये पैकेज न जारी करता, तो क्या उसके पास अन्य विकल्प थे, इस बारे में जानकारों की राय बंटी हुई है।

अर्थव्यवस्था को गति देने वाले विशेष पैकेजों के जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव की छानबीन के लिए लंदन स्थित एक स्वतंत्र एजेंसी विविड इकोनमिक्स ने 17 देशों के विशेष पैकेजों का तुलनात्मक अध्ययन किया। हरित आर्थिकी के लिए परामर्श देने वाली इस एजेंसी की पिछले दिनों जारी रिपोर्ट के मुताबिक 'ग्रीन स्टिमुलस इंडेक्स' यानी हरित प्रोत्साहन सूचकांक में अमेरिका, चीन और भारत समेत पांच देशों का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। अन्य दो देश दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको हैं। इन देशों में भारत का नंबर पांचवा है।

यूं तो भारत के प्रोत्साहन पैकेज का बड़ा हिस्सा पर्यावरणीय लिहाज से सुरक्षित उद्योगों के लिए है लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिहाज से संवेदनशील अन्य उद्योगों के प्रति उसके आग्रह की वजह से उसे सूचकांक में अपेक्षित जगह नहीं मिल पाई है। वनीकरण के प्रस्तावित उपायों की बदौलत भारत ने कुछ 'ग्रीन' अंक जरूर हासिल किए हैं लेकिन कोयला खदानों की कमर्शियल माइनिंग के समर्थन के उसके फैसले और उद्योगों के लिए जंगलों को साफ करने की धड़ाधड़ मंजूरियों के चलते उसे ऋणात्मक 60 'ब्राउन' अंक मिले हैं। खराब स्थितियों मे बसर कर रहे आदिवासी समुदायों के लिए हरित रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रिपोर्ट में भारत के कदमों की सराहना भी की गई है क्योंकि इससे वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और वनीकरण में भी मदद मिलती है।

विविड इकोनमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 17 देशों के प्रोत्साहन पैकेज से उद्योग, ऊर्जा और यातायात सेक्टरों में करीब साढ़े तीन खरब डॉलर निवेश किए जाएंगें लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने वाले ऐसे उपाय पर्यावरण को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बहुत से अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक संगठनों ने देशों से अपील की है कि वे अपनी कोविडोत्तर आर्थिक रिकवरी के लिए प्रोत्साहन पैकेजों को पर्यावरणीय लिहाज से भी संवेदनशील, सुगम और सहज बनाएं। भारत को भी अपना हरित दायरा बढ़ाने के अभियान को नहीं छोड़ना चाहिए। कोविड पश्चात की रणनीतियों के लिए लाजिमी है कि उनकी 'ग्रीन वैल्यू' बनी रहे।

पानी के लिए युद्ध होगा?

रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कि कॉरपोरेट बेलआउट प्रस्तावों पर हरित कर लगना चाहिए। टिकाऊ कृषि में निवेश बढ़ाना चाहिए और हरित निवेशों के लिए ऋण व्यवस्था सुचारू करनी चाहिए। पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखने वाले विकास कार्यों के शोध और विकास के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी देने की सिफारिश भी की गई है। पर्यावरण से जुड़े नियमों और निर्देशों को लचीला करने के बजाय और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट में प्रकट की गई चिंताएं नई नहीं हैं। इनका महत्त्व इस बात में है कि ये आर्थिक पैकेजों की सार्थकता के प्रश्न पर केंद्रित हैं।

पर्यावरणीय आंदोलनों से जुड़े हल्कों में ये चिंता बार बार प्रकट की जा रही है कि कोरोना संकट दरअसल जिस व्यापक सामाजिक संकट को रिफलेक्ट करता है, पर्यावरण उसका ही एक हिस्सा है। इसलिए आज की स्थिति में पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना बड़े आघातों से बचने के लिए पुख्ता रणनीति का हिस्सा होना चाहिए।कोविड संकट के बीच लॉकडाउन की लंबी अवधियों से पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन में गिरावट आई थी और दुनिया के सभी बड़े शहरों में प्रदूषणों के स्तरों में निर्णायक गिरावट देखी जाने लगी थी। यहां तक कहा गया कि वैश्विक बंदी ने ओजोन परत के छेद भी भर दिए थे। हालांकि विडंबना और विरोधाभास ये था कि मनुष्य जीवन पर संकट भी उतना ही भयावह हो चुका था। कोरोना ने अर्थव्यवस्थाओं को तहसनहस किया और आम लोगों की जिंदगियों को छिन्नभिन्न कर दिया। आज खुली आबोहवा और चमकदार आसमान के नीचे ये घाव साफ साफ दिखते हैं, यही कोरोना समय की सबसे बड़ी विडंबना है। प्रदूषकों के स्तरों में अभूतपूर्व गिरावटों ने आने वाले समय के लिए कुछ चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। आंकड़े और वैश्विक संकटों का इतिहास बताता है कि जब जब अर्थव्यवस्था किसी बड़ी मुसीबत से उबरती है तो प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन की दर बढ़ने लगती है और धीर धीरे अपने पुरानी दरों से छलांग लगाती हुई नई खतरनाक ऊंचाइयां हासिल कर लेती है। ये दौर ऐसा ही है और जानकार इसीलिए इकोनमी को गति देने वाले पैकेजों को कुछ चिंता से देख रहे हैं।

**जलवायु परिवर्तन पर कौन कितना गंभीर?**

इकोनमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली पत्रिका में बिट्स पिलानी की पीएचडी स्कॉलर पूनम मूलचंदानी ने पर्यावरणीय संकट और प्रोत्साहन पैकेजों के बीच अंतर्संबंधों की गहन पड़ताल की है। उनके अध्ययन के मुताबिक 1973 और 1979 के तेल संकट हो या 1991 में सोवियत संघ का विघटन या 1997 का एशियाई वित्तीय संकट या 2008 की वैश्विक मंदी- अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कीमत पर्यावरणीय कवच में दरार से चुकानी पड़ी है। और इसमें भी सबसे ज्यादा भुगतते हैं विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। तमाम देश इस बारे में एकजुट रह पाएं, इसके लिए वैश्विक कोशिशें भी अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पा रही हैं।

कोरोना की विकटता ने जलवायु सम्मेलनों को भी चोट पहुंचाई हैं। स्कॉटलैंड में इस साल नवंबर में होने वाला संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अक्टूबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2015 के पेरिस समझौते के बाद इस बैठक का विशेष महत्त्व होता लेकिन तारीख आगे बढ़ जाने का असर विश्व सरकारों की पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़ी योजनाओं और अभियानों पर भी पड़ेगा, उन पर दबाव कम होगा। पर्यावरण के बारे में सोचने से ज्यादा अर्थव्यवस्था संभालने की कोशिशों को तवज्जो मिलेगी। महामारी के बाद उपजे हालात से उत्सर्जनों में कटौती खुदबखुद होती चली जाएगी, ये सही धारणा नहीं है। एक बार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किए जा रहे उपाय युद्धस्तर पर शुरू होंगे तो पर्यावरण पर असर भी दिखने लगेगा। जलवायु परिवर्तन का संकट वैश्विक महामारी की भयावहता का ही एक आयाम है। दोनों को अलग कर देखना सही नहीं होगा। अगर हमारी प्रौद्योगिकीय परियोजनाएं हरित और साफ ऊर्जा आधारित नहीं रही तो संकट और सघन होगा।

ऐसा न हो कि अर्थव्यवस्था तो चमक उठे लेकिन आबोहवा, आसपास और पर्यावरण और समूची जलवायु और अधिक धुंधली और दमघोंटू बन जाए। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों के इस विकट असंतुलन को खत्म करने में ही सबकी भलाई है।

# किसानों तक पहुंचे बिजली गिरने की चेतावनी

**दिलीप लाल**

गर्मियों में जब पुरवैया हवा चलनी शुरू होती है तो सूखे खेत और झुलसे किसानों के लिए राहत भरा माहौल बनाती है। इसी के साथ आती है बंगाल की खाड़ी से उठने वाली ठंडी हवा जो उत्तर भारत में मॉनसून लाती है। अभी मॉनसून का पहला चरण चल रहा है। खेतों में धान के बिचड़े (पौध) तैयार हो गए हैं और निचले इलाकों में जहां पानी जमा है, वहां रोपाई भी चल रही है। इसी बीच खेतों में काम करने वाले किसानों पर आसमान से काल बनकर बिजली भी गिर रही है।

बीते हफ्ते आकाशीय बिजली गिरने से बिहार और उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। बिहार के आपदा प्रबंधन केंद्र ने शुक्रवार शाम तक वज्रपात (ठनका) से 96 की मौत की पुष्टि की है। यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि काफी संख्या में लोग झुलसे भी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में इससे अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। बिहार के गोपालगंज जिले में सबसे अधिक 13 लोगों की मौत हुई है। जिले के अकेले बरौली प्रखंड में चार लोगों की जानें गई हैं। ये चारों अपने खेतों में धान के बिचड़े (पौध) उखाड़ने गए थे, तभी इन पर बिजली गिरी। हालांकि घटना के तीसरे दिन से ही कुछ इलाकों में मृतकों के परिजनों को मुआवजे के रूप में चार-चार लाख रुपये का चेक दिया जाने लगा है। विजयीपुरी के गुमरिया गांव में जब मुखिया और वॉर्ड सदस्य मुआवजे का चेक देने आए, तो वहां का माहौल बड़ा गमगीन बन गया। 12 वर्ष की अफसाना खातून के पिता ने मुआवजे की राशि लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब बेटी ही नहीं रही तो मुआवजा किस-के लिए लेंगे। भारी वर्षा और बिजली गिरने की आशंका को लेकर पूरे राज्य में 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है।

अमेरिका में प्रति वर्ष बिजली गिरने से औसतन 27 लोगों की मौत होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 के बाद से हर साल अपने देश में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से लगभग 2000 लोगों की जानें जाती हैं। पिछले साल सिर्फ उत्तरी भारत में 1300 लोगों की मौत वज्रपात से हुई थी। तब भी यूपी और बिहार में डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थीं। वैसे बिजली बारिश नहीं होने पर भी गिरती है, पर अप्रैल से जुलाई तक इसकी संभावना अधिक रहती है।

आकाशीय बिजली दो तरह की होती है। एक, जिसे हम आसमान में बादलों के बीच कौंधते हुए देखते हैं। यह बहुत ही आकर्षक लगता है। इससे जान-माल का नुकसान नहीं होता है। लेकिन आसमान से जमीन पर गिरने वाली बिजली बहुत तेज और शक्तिशाली होती है। इसमें सूर्य से चार गुना अधिक ताप होता है। वह एक साथ आठ करोड़ मोमबत्ती जलाने जैसा प्रकाश बिखेरती है। सीधी आंख से इसे देख लें, तो आंखें खराब हो सकती हैं। इसलिए बरसात के दिनों में घरों से बाहर नहीं जाने की सलाह दी जाती है। फिर भी बिजली गिरने की घटना ऐसी नहीं है कि इसके नुकसान को न रोका जा सके।

मौसम में होने वाले परिवर्तन और उससे आने वाली आपदा के बारे में पता लगाया जा सकता है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के दामिनी ऐप से बिजली गिरने से पहले ही जानकारी मिल जाती है। लेकिन हमारे सूचना तंत्र ठीक से विकसित ही नहीं हैं। पता लग भी जाता है, तो ग्रामीण इलाकों तक इसकी सूचना नहीं पहुंच पाती है। अमेरिका जैसे देशों में संचार सुविदाएं बेहतर हैं, इसलिए भारत की तुलना में आकाशीय बिजली गिरने से विकसित देशों में मौत की घटनाएं कम होती हैं। बिजली अक्सर खुली जगहों में, जहां घने पेड़ नहीं होते हैं, वहां गिरती है। साथ ही इसके धातु के सामानों, ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों पर और जलाशयों में गिरने की भी आशंका ज्यादा रहती है। शहरों में घर सटे-सटे रहते हैं, उनमें तड़ित चालक लगे रहते हैं, जिससे बिजली गिरने की आशंका कम रहती है। देश में बरसात के दिनों में किसान ही सबसे अधिक घरों से बाहर रहते हैं जिसके चलते इन्हीं पर बिजली कहर बनकर गिरती है।

**विश्व में बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, 2019 में केवल 17 फीसदी किया गया रिसाइकल**

2019 में भारत ने करीब 32.3 लाख मीट्रिक टन ई-वेस्ट उत्पन्न किया था जो कि अफ्रीका के कुल ई-वेस्ट से भी ज्यादा है

दुनिया भर में जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी बढ़ता जा रहा है जिस पर यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी द्वारा एक नई रिपोर्ट 'ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020' जारी की गई है। इसके हवाले से पता चला है कि वर्ष 2019 में 5.36 करोड़ मीट्रिक टन कचरा पैदा किया था। जोकि पिछले पांच सालों में 21 फीसदी बढ़ गया है, जबकि अनुमान है कि 2030 तक इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन 7.4 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा।

दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह तेजी से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खपत है आज हम तेजी से इन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अपनाते जा रहे हैं साथ ही इन उत्पादों का जीवन काल छोटा होने लगा है जिस वजह से इन्हें जल्द फेंक दिया जाता है जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, पुराने को फेंक दिया जाता है इसके साथ ही कई देशों में इन उत्पादों की मरम्मत की सीमित व्यवस्था है, और है भी तो वो बहुत महंगी है ऐसे में जैसे ही कोई उत्पाद ख़राब होता है लोग उसे ठीक कराने की जगह बदलना ज्यादा पसंद करते हैं जिस वजह से भी इस कचरे में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

## मंडियों में सैनधार के लहसुन की बढ़ी मांग,अच्छे दाम मिलने से खिले किसानों के चेहरे

*योगेंद्र अग्रवाल*

उत्तराखंड के सैनधार क्षेत्र के लहसुन की मांग देश की बड़ी मंडियों में बढ़ गई है। किसानों को इसके दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। व्यापारी लहसुन उत्पादकों के घर पहुंचकर ही उनको उनकी फसल के अच्छे दाम दे रहे हैं। सैनधार क्षेत्र का लहसुन इन दिनों 90 से 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। जबकि 15 दिन पहले इसी लहसुन के दाम मात्र 55 से 60 रुपये प्रति किलो थे। तीन-चार दिनों से इसके दामों में भारी उछाल आया है। लहसुन घर पर ही 90 से 100 रुपये प्रति किलो बिकने लगा है। लहसुन को उत्पादकों से खरीदने के लिए आढ़ती, व्यापारी और उनके एजेंट सैनधार क्षेत्र में ही डटे हुए हैं। जो उत्पादकों से उनका लहसुन खरीदकर छोटी गाड़ियों के माध्यम से पड़ोसी राज्य की मंडियों तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में नई मंडियां खुल गई हैं। जिससे लहसुन की मांग वहां बढ़ गई है।

लहसुन उत्पादक राम चंद्र, माता राम, रूपदत्त शर्मा, चंद्रमणी, केवल राम, रविंद्र सिंह, मान सिंह, रामदत्त, रामस्वरूप, बाबू राम और कल्याण सिंह ने घरों से ही व्यापारी उनके लहसुन को 90 से 100 रुपये प्रति किलो तक खरीद रहे हैं। उधर, ददाहू के आढती राजेश ठाकुर, विक्रम सिंह, जगत सिंह और कमलराज शर्मा ने बताया कि आंध्र प्रदेश में लहसुन की मांग बढने के साथ ही लहसुन के दामों मे अचानक से उछाल आया है। जिससे उत्पादक किसान फसल को मंडियों में लाने की बजाए छोटे व्यापारियों को घर पर ही लहसुन बेच रहे हैं।

**एनटीसीए ने जानवरों को सड़क हादसों से बचाने के लिए जारी की कार्य योजना**

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने अपनी संशोधित कार्य योजना प्रस्तुत की है जो तीन वर्षों की अवधि के लिए है इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में पर्यावरण और वन्य जीवन को बचाना है जिसमें टाइगर कॉरिडोर के रास्तों पर उन सभी उपायों को करना है जिससे जानवरों को सड़क हादसों से बचाया जा सके। इसपर एनटीसीए और पर्यावरण मंत्रालय ने एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें वन्य जीवो को बचाने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों को किया जाना है जिसके अंतर्गत यातायात के लिए नियम बनाना, वाहनों की गति को कम करने के उपाय करना, साइनबोर्ड के माध्यम से जानवरों की उपस्थिति को बताना, सड़क के उन हिस्सों की निगरानी करना जहां हादसे होने की सम्भावना ज्यादा है इसके साथ ही रास्तों का उचित प्रबंधन करना शामिल है इस रिपोर्ट को 3 जुलाई 2020 को एनजीटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

# खतरे में हैं दुनिया भर के आदिवासी समुदाय

*अमांडा कूलसन*

संसाधनों के लिए अंतरराष्ट्रीय भूख की वजह से आदिवासी समुदायों के इलाके नष्ट होते जा रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि दुनिया की मानवीय विविधता खोने का खतरा है।

दुनिया भर में रहने वाले 37 करोड़ आदिवासी और जनजाति समुदायों के सामने जंगलों का कटना और उनकी पारंपरिक जमीन की चोरी सबसे बड़ी चुनौती है। वे धरती पर जैव विवधता वाले 80 प्रतिशत इलाके के संरक्षक हैं लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लोभ, हथियारबंद विवाद और पर्यावरण संरक्षण संस्थानों की वजह से बहुत से समुदायों की आजीविका खतरे में हैं। ग्लोबल वॉर्मिंग का असर हालात को और खराब कर रहा है।

जनजातियां विभिन्न तरह की हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वे 90 देशों में फैली हैं, 5,000 अलग अलग संस्कृतियां और 4,000 विभिन्न भाषाएं। इस बहुलता के बावजूद या उसकी वजह से ही उन्होंने एक तरह के संघर्ष झेले हैं, चाहे वे ऑस्ट्रेलिया में रहते हों, जापान में या ब्राजील में। उनका जीवन दर कम है, गैर आदिवासी समुदायों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम है। उनकी आबादी दुनिया की 5 प्रतिशत है लेकिन गरीबों में उनका हिस्सा 15 प्रतिशत है।

**जमीन से वंचित**

सर्वाइवल इंटरनेशनल की फियोना वॉटसन ने डॉयचे वेले को बताया कि विभिन्न समुदायों की सबसे बड़ी चुनौती ये हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन खोती जा रही है। "दुनिया भर में आदिवासी लोगों का पर्यावरण के साथ निकट रिश्ता है। उनकी आजीविका के लिए जमीन अहम है, लेकिन उनका प्रकृति से आध्यात्मिक रिश्ता भी है। औपनिवेशिक काल में जमीनों को हड़पने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज भी जारी है। विवाद और हिंसा की वजह से भी उनकी जमीन हड़पी जा रही हैं और वे रिफ्यूजी बन रहे हैं। कई बार सरकारें आदिवासी इलाकों में वहां रहने वाले लोगों की परवाह किए बगैर बांध बनाने या सड़क बनाने का फैसला लेती हैं। वॉटसन कहती हैं, "आदिवासी समुदायों को अक्सर पिछड़ा माना जाता है और इसका इस्तेमाल सरकारें और बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकास के नाम पर उनकी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए करती हैं।

**ब्राजील की मिसाल**

एक मिसाल दक्षिणी ब्राजील का गुआरानी समुदाय है जिन्हें पशुपालन और गन्ने की खेती के लिए उनकी जमीन से खदेड़ दिया गया है।वॉटसन बताती हैं कि इस समुदाय में आत्महत्या की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है और उस इलाके की जैव विविधता पूरी तरह खत्म हो गई है। विडंबना ये है कि पर्यावरण संरक्षण संस्थाएं भी आदिवासी समुदायों से पूछे बिना उन इलाकों को संरक्षित इलाका बनवा रही हैं, जहां वे सदियों से रहते आए हैं। आदिवासी अधिकारों पर एशिया में भी विवाद हो रहा है, जहां दुनिया की 70 प्रतिशत आदिवासी आबादी रहती है। आदिवासी मामलों के अंतरराष्ट्रीय कार्यदल के अनुसार मलेशिया का बजाऊ लाउट ग्रुप बंजारा समुदाय है जो आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर है। जहां वे मछली पकड़ रहे थे वह इलाका 2004 में तून सकारान मरीन पार्क बना दिया और 2009 से वहां मछली मारने पर पाबंदी है। ऑस्ट्रेलिया के वोलोनगोंग यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार इससे उनके पोषण और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ा है।

**स्वनिर्णय का अधिकार**

इसलिए वॉटसन कहती हैं कि आदिवासी समुदायों के लिए खुद फैसले लेने का अधिकार बहुत मायने रखता है। ये फैसला करने का अधिकार कि वे कैसे जीना चाहते हैं, इसकी अक्सर उपेक्षा की जाती है और इससे गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं।" अभी तक अंतरराष्ट्रीय तौर पर इस पर भी सहमति नहीं है कि आदिवासी की क्या व्याख्या है। इस शब्द का इस्तेमाल 2007 में संयुक्तराष्ट्र की घोषणा में किया गया और तब से दुनिया भर में आदिवासी समुदाय दिखने लगे हैं।

न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय बहुत ही सक्रिय हो गया है। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के जॉन मैककाफरी के अनुसार माओरी भाषा के कोर्स पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। कनाडा में भी आदिवासियों के मामलों पर मीडिया में नियमित रिपोर्ट दी जाती है और वे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि दुनिया भर में आदिवासी समुदायों के साथ गहन संबंध संभव हैं। सरकारों को आदिवासी समुदायों और जनजातियों के महत्व को स्वीकार करना होगा और उनके साथ बातचीत कर भविष्य का रास्ता तय करना होगा।

**कोरोना काल में हड़ताल कर्मियों के स्वास्थ्य एवं कपनी के लिए नकारात्मक :सीएमडी सीसीएल**

रांची : कोयला उद्योग के विभिन्न केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा तीन दिवसीय (02 से 04 जुलाई, 2020) हड़ताल की घोषणा अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए किया गया है। वर्तमान में सभी कंपनियों में कोयला उत्पादन की रफ्तार तेजी पकड़ रही है, ऐसे में कोयला कंपनियों में किसी भी तरह का कार्य रूकने से एक बहुत बड़ी क्षती हो सकती है और देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के सभी प्रयासों पर प्रभाव पड़ सकता है। इस मद्देनजर कोई भी व्यवधान/हड़ताल राष्ट्र की प्रगति में एक प्रतिकूल कदम होगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत हमनें जो कोयला आयात समाप्त करने का लक्ष्य चुना है वह भी इस हड़ताल से प्रभावित होगा।

सीएमडी गोपाल सिंह ने सभी कर्मियों एवं श्रमिक संघों से आग्रह किया है कि इस समय देश कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले कई महीनों से अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इस परिस्थिति में यह हड़ताल कर्मियों के स्वास्थ्य एवं देश और कपनी के आर्थिक हालत के लिए नकारात्मक होगा। अतः आप सभी लोग पुनर्विचार कर हड़ताल को वापस लें।

**गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों का इम्यून सिस्टम भी करता है वायरस से लड़ने की कोशिश**

शोधकर्ताओं के अनुसार गंभीर रूप से कोरोना पीड़ित रोगियों के शरीर में भी टी- कोशिकाओं का उत्पादन होता रहता है जो इस वायरस से लड़ने में मदद करती हैं।कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों का इम्यून सिस्टम भी इस रोग से लड़ने की कोशिश करता रहता है यह जानकारी हाल ही में किये गए एक नए शोध से सामने आई है यह शोध ला जोला इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी (एलजेआई) और इरास्मस यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर (इरास्मस एमसी) द्वारा किया गया है शोधकर्ताओं के अनुसार गंभीर रूप से कोरोना पीड़ित रोगियों के शरीर में भी टी-कोशिकाओं का उत्पादन होता रहता है जो इस वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। ऐसे में कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीन को एंटीबॉडी के साथ-साथ टी-कोशिकाओं पर भी ध्यान देना होगो जो इसके उपचार में मददगार हो सकती हैं यह शोध 26 जून 2020 को जर्नल साइंस इम्युनोलोजी में प्रकाशित हुआ है

गौरतलब है कि दुनिया भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस वायरस के चपेट में आ चुके हैं जिनमें से 5 लाख से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है वहीं 60 लाख से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से उबार चुके हैं भारत में भी इसके 604,641 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से 359,859 ठीक हो चुके है । इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने गंभीर रूप से बीमार 10 मरीजों को चुना थो जिन सभी को नीदरलैंड के इरास्मस यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के आ-ईसीयू में भर्ती कराया गया थो इन सभी मरीजों की हालत इतनी नाजुक थी की इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया थो इनमें से 2 मरीजों की मौत हो गई थी इन सभी मरीजों के इम्यून सिस्टम का गहराई से अध्ययन करने से पता चला कि इन सभी रोगियों के शरीर में कोरोनावायरस से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली ने काम करना शुरू कर दिया थो इनके शरीर ने टी-कोशिकाओं का बनाना शुरू कर दिया थो जो एंटीबॉडी के साथ मिलकर संक्रमण को रोकने ख़त्म करने की कोशिश करने लगी थी

# ड्रोन से टिड्डी दल को काबू में करने वाला पहला देश बना भारत

## एफएओ ने भी की तारीफ

कृषि पर आतंक का पर्याय बने टिड्डी दल को ड्रोन की मदद से काबू करने वाला भारत पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्द एवं कृषि संगठन-एफएओ ने भारत की इस पहल की तारीफ की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर से देश में कहर बनकर भारत पाक सीमा से आ रहे टिड्डी दल को समाप्त करने के लिए राजस्थान में सबसे पहले ड्रोन का प्रयोग किया गया था।

इसके सफल रहने के बाद अब देश के छह टिड्डी प्रभावित राज्यों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान में विभिन्न चरणों में 12 ड्रोन तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बाड़मेर, जैसेलमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर में पांच ड्रोन की सहायता से टिड्डी दल के आक्रमण को काबू में किया जा रहा है।

**टिड्डी दल के नियंत्रण में प्रभावी**

ड्रोन की भारत में सफलता के बाद इसे बड़े पैमान पर टिड्डी प्रभावित अन्य देशों द्वारा भी प्रयोग में लाया जा सकता है। एफएओ ने भारत द्वारा किए गए इस प्रयोग की कार्ययोजना को टिड्डी नियंत्रण में खासी प्रभावी करार दिया है। कृषि और किसान मंत्रालय ने उम्मीद जतायी है कि मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया यह विशेष ड्रोन भविष्य में व्यवसायिक संभावनाओं के साथ देश के लिए बड़ी उपलब्धि भी साबित हो सकती है।

**मेक इन इंडिया की पहल से बना देसी यंत्र**

टिड्डियों के हमले और बड़े पैमाने पर हो रहे नुकसान को देखते हुए मेक इन इंडिया पहल के तहत ऊंचाई पर पेड़ों में जमे बैठे टिड्डों की समाप्ति के लिए वीकल माउंटेड यूएलवी स्प्रेयर तैयार किया था। यह देसी यंत्र सबसे पहले राजस्थान के बीकानेर और अजमेर में प्रयोग किया गया। वहां इसकी सफलता को देखते हुए, मंत्रालय ने इसके व्यवसायिक निर्माण को स्वीकृति देते हुए इसे लॉन्च कर दिया। इस उपलब्धि को अब बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए एक मुश्त उत्पादन के लिए कार्ययोजना की आवश्यकता है। जिससे टिड्डियों पर प्रभावी ढंग से काबू किया जा सके।

**सात राज्यों के 84 जिलों में टिड्डियों का कहर**

इस साल अब तक टिड्डियों के कहर के चलते सात राज्यों के 84 जिलों में बड़े पैमाने पर इनका कई कई बार इनका हमला हो चुका है। जिसमें एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाके पर टिड्डियों के हमले को नाकाम किया जा चुका है। इतना ही नहीं अभी भी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में टिड्डी नियंत्रण का काम जोरों पर है। हमलों की बात करें तो भारत-पाकिस्तान सीमा पर श्री गंगानगर और बीकानेर के रास्ते दो टिड्डी दल ने प्रवेश किया है। इन्हें काबू करने के लिए राज्यों के कृषिविभाग, स्थानीय प्रशासन और बीएसएफ की मदद ली जा रही है।

**नियंत्रण अभियान अभी जारी**

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार 21 जून तक राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 114,026 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के काम को अंजाम दिया जा चुका है। इसमें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी भी नियंत्रण अभियान को चलाया जा रहा है। मंत्रालय के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक टिड्डियों के हमले आने वाले महीनों में तेज होने की संभावनाओं को देखते हुए मंत्रालय एक मुश्त कार्ययोजना पर भी काम कर रहा है, ताकि इनके प्रवेश के साथ ही इन्हें खत्म किया जा सके। इस साल इन टिड्डियों पर दवा छिड़काव के लिये इंग्लैंड से आने वाली मशीनें भी कोरोना संकट के कारण समय पर देश में नहीं आ पायीं जिस कारण से संकट गहरा गया।

# राष्ट्र हित में हड़ताल पर ना जाएं कोयलाकर्मी: प्रल्हाद जोशी

संवाददाता : केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कोल इंडिया के श्रमिक संगठनों से अपील की है कि वे राष्ट्र हित में 2 जुलाई से 4 जुलाई तक प्रस्तावित अपनी हड़ताल वापस ले लें। बुधवार को कोल इंडिया के 04 केंद्रीय श्रमिक संगठनों बीएमएस, एचएमएस, एटक और सीटू के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आहूत बैठक में उन्होंने यह अपील की।उन्होंने कहा कि कमर्शियल माइनिंग के मामले में श्रमिक संगठनों की आशंकाएं निराधार हैं।साथ ही, उन्होंने देश को कोयले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों को सशक्त करने की अपील की।

उन्होंने कोल इंडिया परिवार को आश्वस्त किया कि कमर्शियल माइनिंग से कोल इंडिया का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। कोल इंडिया देश में कोयला उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी थी, है और रहेगी। हड़ताल से कोयला कामगारों का,कंपनी का और सबसे ऊपर देश का भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को बिजली चाहिए, जो पर्याप्त कोयले के बिना संभव नहीं है।उन्होंने कहा कि कोल इंडिया पर भारत को गर्व है, जो देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और अकेले देश का 80% से अधिक कोयला निकाल रही है। फिर भी देश को सालाना लगभग 250 मिलियन कोयले का आयात करना पड़ता है।अपने देश में पर्याप्त कोयला रहते हुए कोयले का आयात किसी पाप से कम नहीं है। कोयले की इसी मांग एवं आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कोयले की कमर्शियल माइनिंग के लिए ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देश चीन सालाना 3,500 मिलियन टन कोयला निकालकर अपने विकास को नई रफ्तार दे रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला रिजर्व रखकर भी चीन आज सबसे बड़ा कोयला उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। चीन को टक्कर देते हुए उससे आगे निकलने के लिए भी यह बेहद जरूरी है कि हम अपने देश में कोयला भंडार का जल्द से जल्द दोहन करें।

# निदेशक तकनीकी(योजना/परियोजना) ने सीसीएल ओबीएस का चेक डॉ. सत्यप्रकाश रंजन को सौंपा

रांची : सीसीएल ऑफिसर्स बेनिवोलेन्ट सोसाईटी (ओ.बी.एस.) की ओर से 02जुलाई को रांची में सीसीएल के निदेशक तकनीकीभोला सिंह ने स्व. डॉ. अकृति, उनके पति डॉ सत्यप्रकाश रंजन को ओ.बी.एस. का रू.4,50,000/- (रू. चार लाख पचास हजार) का चेक प्रदान किया। डॉ अकृति का आकास्मिक निधन विगत 18 जून, 2020 को हो गया था। डॉ सत्यप्रकाश रंजन भी सीसीएल गांधीनगर अस्पातल में ही कार्यरत है। इस अवसर पर सीसीएल सीएमएस डॉ सी.पी. धाम, सीएमएस गांधीनगर, डॉ मंजू मिश्रा, ओबीएस के महासचिव श्री राज कुमार सिंह,कोषाध्यक्ष श्री संजीव प्रसाद,श्री विनय कुमार शंकर, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह एवं अन्य उपस्थित थे।

# घरेलू बागवानी के लिए झारखंड नर्सरी है रांची की पहली पसंद

साहिल कुमार

रांची : आईटीआई इटकी रोड में स्थित 'झारखंड नर्सरी' रांची में काफी विख्यात है जिसका कारण है यहां मिलने वाले लगभग सभी प्रकार के फूल, फल और आयुर्वेदिक पौधे । यह नर्सरी करीब 1 एकड़ में फैली हुई इसकी स्थापना सन् 2004 में हुई थी जिसके संचालक हैं शंभू सिंहे यहां लगभग 14 कर्मचारी कार्यरत हैं जो पौधों की देखभाल करते हैं यहां हर महीने लगभग एक लाख से अधिक पौधों की बिक्री होती है ।

**फूल :** यहां फूल के पौधों की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, यहां गुलाब की करीब 40 किस्म मौजूद हैं जबकि हर प्रकार के फूल आपको यहां मिल जाएंगे सबसे महंगे पौधों में आर्किड करीब 500 और बोनसाई 2500 मैं बिकते हैं । फूलों के बाद यहां शो प्लांट सबसे ज्यादा बिकने वाले पौधे हैं जो हवा भी साफ करते हैं जैसे सनय प्लांट, जेड प्लांट, एरिका पाम, रवीश पाम, क्रासुला, सैंपियन पाम आदि है जिन्हें घर के अंदर या बाहर लगा सकते हैं।

इस नर्सरी की कटहल मोड़ में फैक्ट्री है जहां फूलों की खेती होती है।फल वाले पौधों में आम, जामुन, लीची, शरीफा, नींबू, अंगूर, जाम रूल, नाशपाती, अमरूद और केला मौजूद है इसके साथ ही अंजीर काजू ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो जैसे महंगे फलों के पौधे भी यहां मौजूद है, जबकि औषधीय पौधों में गिलोय, अश्वगंधा, हींग, गुड़मार, नीम, मीठा एलोवेरा, गोलकी, अजवाइन, सतावर आदि पौधे यहां पाए जाते हैं जो कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पुणे, लखनऊ, बनारस आदि शहरों से मंगाए जाते हैं

ग्राहकों की सहूलियत का ख्याल रखते हुए यहां पौधों के अलावा 6 इंच छोटे गमलों से लेकर 24 इंच तक के प्लास्टिक, मिट्टी और सीमेंट के गमले मौजूद हैं जबकि पौधों के विकास के लिए ऑर्गेनिक खाद, रोज मिक्चर और भरमीकंपोस्ट खाद मिलते हैं।

# बीएयू ने कृषि व वानिकी स्नातकों का ससमय परीक्षाफल जारी किया

**रांची :** कोविड - 19 की वजह से लागु लॉकडाउन की अवधि में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्नातक प्रतिष्ठा कृषि एवं स्नातक प्रतिष्ठा वानिकी में अध्ययनरत छात्रों का अंतिम परीक्ष-ाफल ससमय जारी करने में सफल रहा है।

रांची कृषि महाविद्यालय के स्नातक प्रतिष्ठा कृषि पाठ्यक्रम में वर्ष 2016-17 बैच से 13 छात्र एवं 19 छात्राओं सहित कुल 32 छात्रों को सफल घोषित किया गया है। इस बैच में 8।629 ओजीपीए लाकर आयुष लाल दास ने टॉप किया है। डीन कृषि डॉ एमएस यादव ने बताया कि इस बैच में कुल 44 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत थे। इनमें कुल 6 छात्र 9 वें सेमेस्टर में जायेंगे और 6 छात्रों का माइनर विषयों की पुन:परीक्षा में पास होने पर छात्रों का परीक्षाफल घोषित होगा। रांची वानिकी महा-विद्यालय के स्नातक प्रतिष्ठा वानिकी पाठ्यक्रम में वर्ष 2016-17 बैच से 6 छात्र एवं 11 छात्राओं सहित कुल 17 छात्रों को सफल घोषित किया गया है। इस बैच में 8।558 ओजीपीए लाकर अंशु कुमारी ने टॉप किया है। डीन वानिकी डॉ एमएच सिद्दीकी ने बताया कि इस बैच में कुल 20 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत थे। पहले सेमेस्टर के एक विषय में क्वालीफाई नहीं रहने के कारण 3 छात्रों का अंतिम परीक्षाफल रोका गया है। उस विषय की पुन:परीक्षा में पास होने पर छात्रों का परीक्षाफल घोषित होगा।

बीएयू कुलसचिव डॉ नरेंद्र कुदादा ने बताया कि छात्र हितों को ध्यान में रखकर आईसीएआर, नई दिल्ली के दिशा व मार्गदर्शन के अनुपालन में यह परीक्षाफल जारी किया गया है। इसे जारी करने से पूर्व ऑनलाइन माध्यम से दोनों संकायों ने सभी जरूरी प्रक्रिया को पूरा किया। लॉक डाउन की वजह से फैकल्टी के मार्गदर्शन में छात्रों का इएलपी व रावे कार्यक्रम का स-ाक्षातकार व प्रस्तुति ऑनलाइन कराया गया। रिजल्ट समिति द्वारा मूल्यांकन एवं अनुमोदन के बाद ही इसे जारी किया गया है।

कुलसचिव ने कहा कि बीएयू कुलपति सह कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीकी पी की अध्यक्षता में 18 जुन को आयोजित एकेडेमिक कौंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय एवं मार्गदर्शन के अनुसार वर्ष 2016-17 बैच के स्नातक प्रतिष्ठा कृषि एवं वानिकी छात्रों का अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित किया गया। जिसे सभी छात्रों एवं सबंधित को इमेल के माध्यम से भेजा जा चुका है। इस परीक्षाफल को अंतिम रूप देने में दोनों संकाय के डीन एवं फैकल्टी मेम्बर का सराहनीय योगदान रहा है।

# जीवाणु खाद :पोषक तत्व प्रबंधन का सस्ता व उत्तम साधन

.....पेज एक का शेष

**एजोस्पाइरिलम कल्चर:** यह कल्चर भी ये जीवाणु हवा से नेत्रजन व अघुलनशील गैस लेकर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते है। इसमें गाठें नहीं होती है। खरीफ के मौसम में धान, मोटे अनाज तथा गन्ने एवं रबी मौसम में गेहूँ व जौ फसल के लिए विशेष उपयोगी होते है। इसके उपयोग से उपज में 10-12 प्रतिशत की वृद्धि तथा 15-20 किलो प्रति हेक्टेयर नेत्रजन की बचत की जा सकती है। बीजोपचार हेतु प्रति एकड़ 200 ग्राम (दो पैकेट) एजोस्पाइरिलम कल्चर की आवश्यकता होती है।

**नील हरित शैवाल:** यह एक जैविक स्रोत है, जिसका उपयोग धान की खेती में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये शैवाल मिट्टी के सदृश्य सूखी पपड़ी के टुकडे के रूप में होते है। पानी से भरे खेत में धान फसल हेतु यह विशिष्ट लाभकारी होता है। इसके प्रयोग से उपज में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि तथा 20-30 किलो प्रति हेक्टेयर नेत्रजन की बचत की जा सकती है। इसे धान रोपाई के एक सप्ताह के बाद खेत में करीब 4 से ामी। पानी भरकर 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लाया जाना चाहिए।

कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से सभी प्रकार के जीवाणु खाद का उत्पादन वैज्ञानिकों के देख-रेख में की जाती है। किसान द्वारा इसका सीधा क्रय विभाग से निर्धारित दर पर किया जा सकता है। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत भी किसान जीवाणु खाद को प्राप्त कर सकते है।

# एसोचैम का नॉलेज मैनेजमेंट वर्चुअल मीट आयोजित

रांची :नॉलेज मैनेजमेंट वर्चुअल मीट ''2nd एडिशन स्किल 2.0- ए फ्यूचर स्किल पर्सपेक्टिव नेक्स्ट वेव ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स, का आयोजन 30 जून, सुबह 11 बजे किया गया। स्किलिंग सेक्टर लॉकडाउन से बहुत प्रभावित हो रहा है और उसे भारी नुकसान हो रहा है और इस प्रक्रिया में नए तरीकों और प्रौद्योगिकी के समावेश के साथ पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ASSOCHAM ने 30 जून को नॉलेज मैनेजमेंट वर्चुअल मीट ''2nd एडिशन स्किल 2.0- ए फ्यूचर स्किल पर्सपेक्टिव नेक्स्ट वेव ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स, का आयोजन किया।

इसका उद्देश्य कौशल विकास के क्षेत्र में नए सुधारों और डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग के बारे में चर्चा करना था। परिचय भाषण,भरत जायसवाल, क्षेत्रीय निदेशक, एसोचैम द्वारा दिया गया। सुश्री माया स्वामीनाथन सिन्हा, निदेशक / संस्थापक, सीएमसी कौशल और सह अध्यक्ष ASSOCHAM झारखंड राज्य विकास परिषद ने सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रौद्योगिकी उपकरणों पर भी अपना दृष्टिकोण दिया जो उपलब्ध हैं और वे भारत में कौशल क्षेत्र में प्रशिक्षण मॉड्यूल में कैसे एकीकृत होने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ सिफारिशें भी जोड़ीं, जैसे कि नए उद्योग और क्षेत्र को देखने की जरूरत है। तकनीकी सत्र के दौरान स्किलिंग क्षेत्र के लिए विभिन्न सिफारिशों पर भी चर्चा की गई।

उद्योग के तकनीकी विशेषज्ञों ने भी इस विषय पर अपने विचार साझा किए। जिसमें अशोक मेहता, मुख्य व्यवसाय अधिकारी, वेटिव लैब्स लिमिटेड, नीरज सिन्हा, प्रमुख - खुदरा और उपभोक्ता बैंकिंग, SBM Bank India Ltd. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ। सुमीत सुसिलान, सुजय गोपाल राव, मुख्य प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, प्रमुख वक्ता रहे।

# वन संपदा व पर्यावरण का सुदृढ दर्शन वन महोत्सव का मूल मंत्र

ज्योति कुमारी

जुलाई महीने का प्रथम सप्ताह वन महोत्सव को समर्पित होता है। कोरोना प्रकोप के बावजूद भारत के कई राज्यों में 71वे वन महोत्सव का स्वागत वृक्ष लगा पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण का संकल्प ले कर किया गया। 1 से 7 जुलाई तक मनाने जाने वाले इस वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में, भारत के कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा एक जन आन्दोलन के रूप में की गयी थी। और इस महोत्सव का एक मात्र उद्देश्य था देश में वृक्षों की बढ़ोतरी कर पर्यावरण को बचाना। आज भी इस महोत्सव को इसी उद्देश्य के साथ मनाया जाता है।

भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार वनों की भूमि से पहचाने जाने वाला झा-रखंड राज्य का कुल वन क्षेत्र 23,605 वर्ग किमी तक फैला हुआ है। जिसमें आरक्षित वन 4,387 वर्ग किमी, संरक्षित वन 19,185 किमी और अवर्गीकृत वन 33 वर्ग किमी क्षेत्र घेरते हैं। राज्य में पर्यावरण और वनों को संतुलित रखने हेतु हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना आवश्यक है। और इसी सोच के साथ वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री जन-वन योजना की शुरुवात हुई, जिससे झारखंड राज्य का वन क्षेत्र 29.45 प्रतिशत से बढ़ कर 29.62 प्रतिशत हो गई है।

जन-वन योजना का आधार था राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना जिससे अधिसूचित वनों पर दबाव कम पढ़े और इसी के साथ किसान अपनी खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण कर अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर सकें। इस योजना के तहत ग्रामीण, अपनी निजी भूमि पर काष्ठ प्रजातियों के पेड़,शीशम, सागवान, गम्हार, क्लोनल, यूकलिप्टस, एकासिया एवं फलदार प्रजातियों यथा कलमी आम, कटहल, अमरूद, आंवला, बेल एवं लीची का वनरोपन कर सकेते हैं। शुरुवात मे इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को वृक्ष लगाने व उसके देखरेख का 50 प्रतिशत खर्च वन विभाग द्वारा देने का निश्चित किया गया था, पर 2018 मे फिर उसे बढ़ कर 75 प्रतिशत कर दिया गया। राज्य में वन क्षेत्र की रेखा में जहाँ एक ओर बढ़ोतरी हुई है तो वही दूसरी ओर वृक्षों में कमी भी आई है। योजना की जानकारी जन तक न पहुँच पाने के कारण इस योजना से काफी कम लोग जुड़े हैं। राज्य के कई जिले ऐसे है जहां वन क्षेत्र काफी कम हैं जैसे जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गिरीडीह, दुमका, धनबाद और गोड्डा जैसे जिलों मे वन क्षेत्र 20 प्रतिशत से कम हैं। झारखंड की लुप्त होती पौधों व वनस्पतियों को बचाने के लिए घने जंगलों का होना अति आवश्यक है।

विकास के होड़ ने पेड़ों की कटाई जारी रखा है। इसे संतुलित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। झारखंड में इस योजना के तहत रखे गए लक्ष्य की पूर्ति अभी तक नहीं हुई है। इस वर्ष वन महोत्सव का उत्सव शांत पड़ा है। देश व राज्य की हरियाली और वन संरक्षण की दिशा में हम अपना योगदान कब देंगे ताकि वन महोत्सव का निर्धारित लक्ष्य सार्थक हो सके।

**मौसुनी आइलैंड़, बक्खली,में वर्कशॉप का आयोजन किया गया**

***प्रकृति के बीच जमीं फोटोग्राफर की भीड़***

पिंटू कुमार

canon के मेंटर अनूप गोह के द्वारा तीन दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया इस वर्कशॉप में 51 प्रतिभागियों ने देश के अलग -अलग राज्यों से भाग लिया वर्कशॉप में photography .cinometicgraphy. pho-toshop के बारे में जनकारी दिया गया मेंटर ने अपने संबोधन में कहा की आज के समय एक फोटो लेना .कैमरा से बहुत ज्यादा मुश्किल नही हैं लेकिन एक अच्छा फोटो लेना बहुत मुश्किल हैं (

राजा अवस्थी ने कहा की रोजना एक वीडिओ देखें ओर उसे कुछ नया सीखने का कोशिश करें ओर नए तरीके से अच्छा वीडियो ले . मोहित जयपुरी (फोटोशॉप मेंटर )ने कहा की आप फोटोशॉप के माध्यम से अच्छा फोटो बना सकते हैं,फोटो में नये नये रंगों को डाल सकते हैं एस वर्क शॉप में रांची से धर्मवीर, पिंटू,कौशिक,अभिषेक आदि ने भाग लिया वर्क शॉप का सम्पन्न सफलता पूर्वक हुआसभी प्रतिभागियों को certificate दे कर सम्मानित किया गया।

# फोटो न्यूज

## कोरोना की मार झेलता दशम जलप्रपात

**सौरभ कुमार मुंडा**
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, राँची विश्वविद्यालय

रांची टाटा मार्ग पर स्थित दशम जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए राज्य भर में प्रसिद्ध है। कांची नदी पर अवस्थित यह जलप्रपात 144 फुट की ऊंचाई से गिरते हुए काफी मनोरम दृश्य पैदा करती है। मानसून में होने वाली बारिश से इसका जलस्तर काफी बढ़ जाता है जो सैलानियों को अपनी ओर खींच लाता है। इस साल भी मानसून के आते ही यह अपनी छटा बिखेरने लगा है। हरे भरे वनस्पतियों के बीच यह और भी खूबसूरत लगता है। पर इस साल इसकी सुंदरता को निहारने कोई भी सैलानी नहीं पहुंच रहा। इसका मुख्य कारण है- वैश्विक स्तर पर महामारी कोरोना का प्रकोप।

कोरोना महामारी ने जिस तरह से हमारी दैनिक जीवन को प्रभावित किया है ठीक उसी तरह इसने तमाम छोटे बड़े उद्योग के साथ साथ पर्यटन को भी खासा प्रभावित किया है। पर्यटन के क्षेत्र से होने वाली राजस्व में भारी गिरावट का आई है, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बुंडू थाना क्षेत्र के तैमारा गांव स्थित दशम जलप्रपात भी इस महामारी का दंश झेल रहा है। भ्रमण के शौकीन लोग घरों में दुबके पड़े है। जहां मानसून के समय हज़ारों की संख्या में सैलानी दशम जलप्रपात पहुँचते थे, अभी उनकी संख्या न के बराबर है। इसका असर अर्थव्यवस्था पर तो पड़ ही रह है साथ साथ गांव के क्षेत्रीय लोगों द्वारा लगाए जाने वाले दुकान, स्टाल और पार्किंग से होने वाली कमाई भी ठप्प है। ग्रामीणों को अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे विकल्पों का सहारा लेने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है इस तरह से देखा जाए तो कोरोना महामारी ने न सिर्फ हमारी आपकी निजी जिंदगी को प्रभावित किया है बल्कि बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित किया है जिसका सीधा असर हमारे दैनिक जीवन मे देखने को मिलेगा।

# डॉक्टर्स डे पर रांची रेल मंडल पर कार्यरत सभी डॉक्टर्स के कार्य कों सराहा गया

कलावंती सिंह

डॉक्टर्स के समर्पण कार्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी एवं उनके लगन को सम्मान एवं आदर देने के लिए प्रतिवर्ष 01 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता हैं। इसी क्रम में राँची रेल मंडल पर कार्यरत सभी डॉक्टर्स के कार्य कों कोविड-19 के लिए सराहा गयाे विश्व में डॉक्टरों को बहुत सम्मान दिया जाता हैं समाज में इनका स्थान पूजनीय होता हैं तथा इनकी तुलना ईश्वर से भी कि जाती हैं` डॉक्टरों ने यह दर्जा मनुष्य जीवन को बचाने के लिए अपने समर्पित कार्य से प्राप्त किया हैं।

रांची रेल मंडल पर कोरोना महामारी के संकट में डॉक्टर्स ने अहम् भूमिका निभाई हैं। प्रतिवर्ष 01 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी संकट के वजह से स्तिथि अलग हैं पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित हैं जिस-के कारण 24 मार्च 2020 से पूरे भारत देश में लॉकडाउन कर दिया गया था, इस दौरान शहर के लगभग सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों का उपचार करना लगभग बंद हो गया था, लेकिन हटिया स्थित राँची मंडल के अस्पताल में ओपीडी एवं चिकित्सा की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रही साथ ही मंडल के राँची, हटिया, मुरी एवं लोहरदगा स्टेशनों एवं अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रही। लॉकडाउन के दौरान राँची रेल मंडल पर कार्यरत सभी डॉक्टर ने पूरी निष्ठा एवं लगन से कोविड-19 के रोकथाम हेतु योगदान दिया।

हटिया स्थित मंडल अस्पताल को को-विड-19 अस्पताल घोषित कर दिया गया एवं हटिया स्थित आरपीएफ बैरक में 50 बेड का सभी सुविधाओं से युक्त आइसोलेशन वार्ड कोविड सेंटर बनाया गया जिसमें मंडल के सभी डॉक्टर अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर हैं, साथ ही अपने कार्य के प्रति निष्ठा दिखाते हुए मरीज़ों के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहे ।इसके पश्चात रांची रेल मंडल पर दिनांक 01 मई 2020 से श्रमिक ट्रेनों का, 14 मई से राजधानी स्पेशल ट्रेनों का तथा 01 जून से जनशताब्दी ट्रेनों का परिचालक शुरू किया गया` इन ट्रेनों में श्रमिकों एवं यात्रियों के आगमन एवं प्रस्थान के दौरान राँची रेल मंडल के डॉक्टर्स कि टीम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा।

श्रमिक ट्रेनों एवं अन्य स्पेशल ट्रेनों द्वारा आने तथा जाने वाले यात्रियों के लिए कोरोनावायरस के प्रोटोकॉल का पालन करना, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करना, सामाजिक दूरी का पालन करना एवं हाथों को सैनिटाइज कराना तथा यह सुनिश्चित करना की आने तथा जाने वाले यात्रियों में कोरोनावायरस के लक्षण नहीं है, साथ ही इन ट्रेनों से यात्रा कर रहे यात्रियों मैं किसी यात्री को बीमार पाया गया तो उसे तुरंत मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। कोविड-19 के संक्रमण के इस दौर में रांची रेल मंडल के डॉ जी सी हेम्ब्रम मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल अस्पताल हटिया, डॉक्टर संजीव कुमार अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रांची, डॉक्टर झरिया कच्छप अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मुरी, डॉक्टर एन लकडा, डॉक्टर बी साहु, डॉ विवेक सहाय, डॉक्टर सलोनी, डॉक्टर नीलम दयाल, डॉ एस कपूर, डॉक्टर भुजबल, डॉक्टर पी मिश्रा तथा नर्सिंग एवं पैरामे-डिकल स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

## शहरो की ओर पक्षियों की उड़ान

**एनि**

इस लॉकडाउन के समय शहरों में लोगो की भीड़ और शोरगुल कम होने के कारण से कई प्रकार के वैसे पक्षी नजर आ रहे हैं जो पहले कभी दिखाई नहीं देते थे। ये पक्षी ऐसे विचरण कर रहे हैं जैसे मानो उन्हें किसी का डर - भय नहीं और वो आजादी के साथ इधर उधर उड़ते नजर आ रहे हैं।

विकास की होड़ ने उनके निवास का विनाश कर दिया है। जहां एक भी पेड़ नहीं छोड़ा जाता है बड़े - बड़े पुराने वृक्षों को काट दिया जाता है। एक पुराना पेड़ कई चिड़ियों का घर होता है। ऐसे में पक्षियों का आश्रय खत्म होते गया, शोर और प्रदूषण में इन्होंने अपना घर खो दिया है । अपने घोंसले,अपने भोजन का स्रोत,अपनी सुरक्षा, अपना आश्रय खोता देख यह शहरों से पलायन कर गये हैं। लेकिन लॉक-डाउन मे जैसे हमे कैद कर दिया,वही दूसरी ओर पशु-पक्षी के लिए पूरे वातावरण में बेझिझक घूमने के द्वार भी खोल दिये । अब शांत और साफसुथरे वातावरण में इनका फिर से शहरों की ओर आना दिख रहा है अभी ये बेफिक्र होकर घूम रहे हैं भले वो क्षणिक हीं क्यों न है।

छात्रा :पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, राँची विश्वविद्यालय

# लॉकडाउन के बीच खेतों में लौट रही है रौनक

**निकिता कुमारी**

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। इस दिशा में **मॉनसुन के आते ही खेतों में जुताई और बुनाई का काम शुरू** किसानों का योगदान महत्वपूर्ण है और अपने इसी दायित्व को पूरा करने के लिए किसान बखूबी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेतों में उतर चुकें हैं।

रांची से 55 किमी दूर सिल्ली ऐसा ही एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। जहां एक ओर लॉकडाउन की वजह से सभी काम-काज रुके हुये हैं वहीं दूसरी ओर किसानों के कदम खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं, और किसानों ने धान की फसल के लिए जुताई और बुनाई का काम शुरू कर दिया है।

किसान उपेंद्र नाथ महतो कहते हैं कि खेती से ही उनके परिवार का भरण-पोषण होता है और उनके साथ उनका पूरा परिवार खेती में उनकी मदद करता है। वे मौसमी सब्जियों की भी खेती करते हैं।

**लॉकडाउन से फ़ायदे** :लॉकडाउन के वजह से जो

लोग अपने घरों और शहरों से बाहर थे, वे अपने घर वापस आ चुके हैं। ऐसे में जिस परिवार के आधे सदस्यों पर खेती की जिम्मेदारी थी वो अब पूरे परिवार के साथ सहजता से खेती कर सकेंगे। इसके साथ ही गांवों में रौनक आ गई है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेती करने में जुट गए हैं। धान की खेती के साथ ही मकई और सिज़नल सब्जियों पर भी अच्छी तरह ध्यान दें रहे हैं।

# बिचाहातु टेटे टुंगरी को पर्यटन स्थल बनाने का हुआ निर्णय

सिदाम महतो

बुण्डूः प्रखण्ड के लेपाडीह मौजा(थाना नम्बर 11) पर अवस्थित बिचाहातु टेटे टुंगरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर के बीते बुधवार को ग्राम सभा की गई।ग्राम सभा की शुरुआत वृक्षारोपण करने के साथ की गई। टेटे टुंगरी को पर्यटन सह योग स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विचार विमर्श किया गया । सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह जगह योगाभ्यास एवं पर्यटन के लिए उपयुक्त जगह है। टेटे टुंगरी के लिए चार दीवारी, शेड निर्माण, पेयजल हेतु बोरिंग चापाकल, चढ़ने- उतरने के लिए सीढ़ी एवं शिव मन्दिर का निर्माण का निर्णय लिया गया।साथ ही समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष-लोहरा महतो(पूर्व प्राचार्य), उपाध्यक्ष राजकिशोर सिंह मुंडा, रघुनाथ महतो, सचिव -हरिहर महतो (समाजसेवी),सह सचिव सुलेखा कुमारी (वार्ड सदस्या),रघुवर सिंह मुण्डा ( ग्राम प्रधान बिचाहातु ), महाबीर महतो ( एडकेया वार्ड सदस्य ), दलगोविन्द सिंह मुण्डा ( ग्राम प्रधान सुमानडीह ), गोपाल मुण्डा ( ग्राम प्रधान बुरूडीह ), प्रदीप महतो ( पंचायत समिति सदस्य ) सुमानडीह ,कोषाध्यक्ष -शैलेश कुमार महतो,सलाहकार -दिलीप साहू , शशिभूषण सिंह मुंडा,मीडिया प्रभारी धनु नाग।

टेटे टुंगरीः बुण्डू प्रखण्ड के लेपाडीह मौजा थाना नम्बर- 11 में टेटे टुंगरी चन्चालू पहाड़ के पूर्वी छोर पर अवस्थित है। टुंगरी के ऊपर बरगद का एक पेड़ है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। सुबह- शाम आस-पास पास के लोग टहलने के लिए आते हैं। टुंगरी के ऊपर से उगते हुए सूरज और ढलती शाम को शाम को देखना मन को बहुत ही आनन्दित कर देता है।

# 55 हजार से अधिक ग्रामीणों पर विस्थापन का खतरा

अनिल अश्विनी शर्मा

***जल विद्युत परियोजनाओं से विस्थापित हुए हजारों परिवारों का अब तक राज्य सरकार पुनर्वास नहीं कर पाई है***

मध्यप्रदेश के मंडला जिले का गांव सिंगापुर, जिसके प्रभावित होने का खतरा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दिल्ली और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड के बीच हुए अनुबंध के बाद 99 गांवों के लगभग 55 हजार लोगों पर विस्थापन का खतरा बढ़ गया है। इनमें लगभग 50 गांव आदिवासियों के हैं, जहां लगभग 30 हजार आदिवासी रह रहे हैं।

दरअसल, पिछले दिनों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दिल्ली और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश के बीच 22 हजार करोड़ का अनुबंध हुआ है। इसमें नर्मदा घाटी की कुल 12 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें चार जल विद्युत और 8 बहुद्देश्यीय (जल विद्युत और सिंचाई दोनों) योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से राज्य को 225 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी।

अब तक राज्य सरकार 4 परियोजनाओं की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बनाई है। इन 4 परियोजनाओं की वजह से लगभग 55 हजार ग्रामीण प्रभावित होंगे, जबकि अभी आठ परियोजनाओं की डीपीआर तैयार नहीं हुई, जिसका असर बाद में दिखाई देगा। ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना 1980 के दशक से शुरू हुई थी, जिसके अंतर्गत 29 बड़े बांधों को बनाया जाना था। अब तक इनमें से आठ का निर्माण हो चुका है। और इनमें से लगभग 625 गांव के 96,500 परिवार विस्थापित हुए यानी लगभग 4,82,500 ग्रामीण अब तक विस्थापित हो चुके हैं।

यहां सबसे बड़ा सवाल है कि राज्य स-रकार अब तक इन हजारों परिवारों का तो ठीक से पुनर्वास कर नहीं पाई है, ऐसे में नए 55 हजार और ग्रामीणों को विस्थापित कर कैसे उनका पुनर्वास होगा। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि इसके अतिरिक्त इस परियोजना के पूरा होने के बाद उसके आसपास के लगभग सात किलोमीटर की परिधि में आने वाले 34 और गांवों के सघन जंगल 4,774, कृषि भूमि 3,860 हेक्टेयर और कुल 66 जल स्रोत अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। नर्मदा घाटी में मध्यप्रदेश स-रकार द्वारा 29 बड़े बांध प्रस्तावित हैं, इसमें बरगी, तवा, बारना, इंदिरा सागर(पुनासा), ओंकारेश्वर, महेश्वर, मटियारी, हालोन बांध का निर्माण हो चुका है। हालोन बांध से मंडला एवं बालाघाट जिले के अधिकतर विस्थापित परिवार आज भी पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं।

बरगी बांध के उपर बुढनेर,राघवपुर, रोसरा और बसानिया बांध बनना बाकी है। भारत सरकार और मध्यप्रदेश के बीच हुए अनुबंध के अन्तर्गत डिंडोरी और मंडला जिले के राघवपुर, रोसरा एवं बसनिया बांध से 65 मेगावाट जल विद्युत परियोजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

इन विद्युत परियोजनाओं से 8,367 हैक्टर क्षेत्र में बसे किसानों को विस्थापित किया जाएगा। इन तीन परियोजनाओं पर पूर्व में कुल लागत 1,283.12 करोड़ अनुमानित थी, लेकिन अब इसकी लागत दोगुना से ज्यादा आंकी जा रही है।

साभार : डाउन टू अर्थ

# अंटार्कटिका के नाजुक इकोसिस्टम में पहुंचा प्लास्टिक

एजेंसियां

रिसर्चरों ने धरती के सबसे सुदूर इलाकों में शामिल अंटार्कटिका के फूड सिस्टम में माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया है। पहले से ही जलवायु परिवर्तन से खतरे में पड़ा यहां का ईकोसिस्टम क्या इससे बच पाएगा?

पहली बार वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों के अंदर से माइक्रोप्लास्टिक मिला है। 'बायोलॉजी लेटर्स' नाम के साइंस जर्मन में छपी इस स्टडी के लेखक ने लिखा है कि यहां की धरती पर मौजूद फूड चेन में प्लास्टिक के पहुंचने से "ध्रुवीय ईकोसिस्टम पर और दबाव बनेगा जो पहले से ही इंसानी दखलअंदाजी बढ़ने और जलवायु परिवर्तन की परेशानियां झेल रहा है।"

**क्या होते हैं माइक्रोप्लास्टिक?**

यह प्लास्टिक के ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। दुनिया भर

में नदियों और सागरों में इस समय करीब 15 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा घुला होने का अनुमान है। यह जब लहरों और अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण टूट-टूट कर और छोटा हो जाता है तो माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। यह माइक्रोप्लास्टिक सागर के पानी के साथ फिर तलछटी, तटीय इलाकों और समुद्री जीवों में पहुंच जाता है।

**स्टडी कैसे कराई गई?**

इटली की सिएना यूनिवर्सिटी ने रिसर्च टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने इलाके के किंग जॉर्ज आइलैंड से लाए गए एक सिंथेटिक फोम के टुकड़े की जांच की, जो लंबे समय से वहां पड़े होने के कारण मॉस और लाइकेन जैसे समुद्री जीवों से लिपटा था। फोम के सैंपल के चारों ओर लिपटे सूक्ष्मजीलों की जांच से सामने आई जानकारी। इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीक की मदद से रिसर्चरों ने पाया कि इनमें से एक जीव के भीतर पॉलीस्टाइरीन से बने फोम का अंश पहुंचा हुआ था। यह जीव स्प्रिंगटेल कहलाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है क्रिप्टोपाइगस एंटार्कटिकस। यह सूक्ष्मजीव अंटार्कटिका क्षेत्र में लगभग उन सब जगहों पर पाया जाता है, जो हमेशा बर्फ से ढके नहीं रहते। यह जीव लाइकेन और माइक्रो-एल्गी को खाता है।

रिसर्चरों ने बताया कि अपने इसी भोजन के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक स्प्रिंगटेल के भीतर पहुंचा होगा। रिसर्चरों का मानना है कि प्लास्टिक इस रास्ते से अब तक अंटार्कटिका की जमीन पर पाए जाने वाले जीवों के पूरे सिस्टम में प्रवेश कर चुका होगा।

**प्लास्टिक प्रदूषण से कैसा खतरा**

सागरों में प्लास्टिक का कचरा होने की जानकारी पहले से ही थी। लेकिन अंटार्कटिका जैसे इंसानी आबादी से दूर दराज के इलाकों की धरती में भी इसका पाया जाना नई बात है। वैज्ञानिकों कहते हैं कि यहां भी प्लास्टिक पहुंचने का मतलब हुआ कि इससे अंटार्कि-टका के बेहद नाजुक संतुलन वाले ईकोसिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है।

यह इलाका पहले से ही जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान से अपने ग्लेशियर गंवा रहा है। इसके अलावा रिसर्च पोस्ट, मिलिट्री सेंटर और पर्यटन के कारण बीते सालों में यहां इंसानी गतिविधियां भी काफी बढ़ गई हैं। इसलिए हैरानी नहीं कि साउथ शेटलैंड के द्वीपों में से एक किंग जॉर्ज आइलैंड के आसपास का इलाका पूरे अंट-ार्कटिका के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक" बन चुका है।

E ZONE CARE

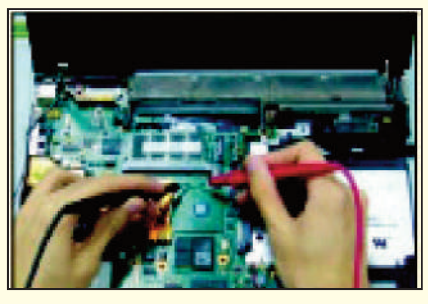

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road,
Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी )आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।